प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक-1 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 31-7 जनवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

धर्मशाला रैली के बाद और बढ़ी जयराम की चुनौतियां

शिमला/शैल। क्या भाजपा में गुटबन्दी सुलगना शुरू हो गयी है? यह सवाल सरकार द्वारा धर्मशाला में एक साल पूरा होने के मौके पर मनाये गये जश्न के बाद अचानक चर्चा में आ गया है। क्योंकि इस मौके पर शान्ता, धूमल और नड्डा को मंच से जनता को संबोधित करने का अवसर नही मिल पाया। यही नही इस अवसर पर जो प्रदर्शनी आयोजित की गयी थी उसमें प्रधानमन्त्री के साथ जे.पी. नड्डा तक शामिल नही हो पाये। क्योंकि प्रधानमन्त्री के साथ प्रदर्शनी में कौन साथ रहेगा और मंच कौन -कौन सांझा करेगा इसकी सूची राज्य सरकार तैयार करके पीएमओ तथा एसपीजी को भेजती है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की सूची में नड्डा का नाम ही शामिल नही किया गया था। इस कारण से नड्डा यह प्रदर्शनी देखने और इसमें बुलाये गये लाभार्थियों को नही मिल पाये। नड्डा का नाम राज्य की सूची से जानबुझ कर बाहिर रखा गया या अनजाने में छूट गया इसको लेकर कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं। लेकिन यह जो कुछ भी घटा है उसका संदेश बहुत ज्यादा सकारात्मक नही गया है। क्योंकि इस रैली के मंच से मोदी के आने के बाद केवल दो ही भाषण हुए। एक जयराम का और दूसरा स्वयं मोदी का। यहां तक की धन्यवाद भाषण भी नही हुआ। यह सब जितनी जल्दी निपटाया गया उसके लिये उसी दिन संसद में तीन तलाक पर बहस और मतदान से पहले संसद में पहुंचने का कवर लिया गया। लेकिन यहां समय इतना भी कम नही था कि शान्ता और धूमल से दो-दो मिनट का संबोधन न करवाया जा सकता था। यही नही मोदी ने भी अपने भाषण में शान्ता-धूमल का केवल रस्मी तौर पर ही नाम लिया। जबकि पहले मोदी शान्ता-धूमल की सरकारों के वक्त हुए काम का जिक्र जरूर किया करते थे। लेकिन इस बार मोदी का पूरा फोक्स जयराम पर ही रहा। जयराम के एक वर्ष में अनेकों विकास योजनाएं बनी है यह कह कर मोदी ने यह साफ संकेत दिया कि अब उनके लिये हिमाचल में जयराम ही सब कुछ हैं। वह जयराम को अपना परम मित्र बता गये। जयराम ने भी इसके बदले में मोदी को आश्वस्त कर दिया कि वह हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े मिलेंगे। मोदी हिमाचल के प्रभारी भी रहे चुके हैं और इस दौरान जो जो मोदी के घनिष्ठ रहे हैं उन्हें जयराम ने भी 32 सदस्यी योजना आयोग में स्थान देकर स्पष्ट कर दिया है कि वह मोदी की अपेक्षाओं पर पूरे खरे उतरेंगे।

धर्मशाला की रैली के इस सारे घटनाक्रम से यह साफ हो जाता है कि मोदी जयराम को प्रदेश में खुला हाथ दे गये हैं। इस नाते अब प्रदेश से चारों लोकसभा सीटें जीत कर मोदी के हाथ मजबूत करना जयराम की नैतिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी बन जाती है। आगे लोकसभा के लिये उम्मीदवार कौन होंगे यह तय करने में भी जयराम की भूमिका अहम होगी। क्या पूराने ही उम्मीदवार फिर से मैदान में होंगे या कोई नये चेहरे होंगे यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। यह साफ हो गया है कि लोकसभा जीतना अब केवल जयराम की ही जिम्मेदारी होगी। लेकिन क्या जयराम मोदी की अपेक्षाओं पर खरे उतर पायेंगे यह एक बड़ सवाल बनता जा रहा है क्योंकि इस समय जयराम की सरकार पर सबसे जयादा प्रभाव विद्यार्थी परिषद और आरएसएस का माना जा रहा है। क्योंकि मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर तथा पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती और कई अन्य मंत्री स्वयं विद्यार्थी परिषद के नेता रह चुके हैं। इस नाते विद्यार्थी परिषद का वर्तमान नेतृत्व भी सरकार पर पूरा दखल बनाये हुए है। प्रदेश के संघ प्रमुख संजीवन तो सचिवालय में अधिकारियों और मन्त्रियों के साथ बैठक में भाग ले चुके हैं इसी के साथ मुख्यमन्त्री के गिर्द कुछ अधिकारियों का भी पूरा घेरा है। मुख्यमन्त्री के विश्ववस्त पत्रकार इन अधिकारियों की प्रशसां के पुल भी बांध चुके हैं। भले ही स्तुतिगान के बाद अन्य अधिकारियों ने नियमों के दायरे में रह कर सरकार के आदेशों की अनुपालना करने की नीति अपना ली है। इस तरह मुख्यमन्त्री के गिर्द घेरा डाले बैठे कुछ अधिकारी और कुछ पत्रकारों का दखल आज सबकी चर्चा का विषय बना हुआ है।

इस परिदृश्य में यह बड़ा सवाल हो जाता है कि क्या यह सब लोग मिलकर जयराम और भाजपा को प्रदेश की चारों लोकसभा सीटें दिला पायेंगे? इसके लिये यदि एक साल पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहले यह आता है कि जब जयराम ने सत्ता संभाली थी तब प्रदेश का कर्जभार 45000 करोड़ था जो अब 50973 करोड़ को पहुंच गया है । इस एक वर्ष में सरकार कितनों को रोज़गार दे पायी है इसका पता इसी से चल जाता है कि आज शिक्षा विभाग के अध्यापकों के खाली पद उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद नही भरे जा सके हैं। बिजली बोर्ड में आऊट सोर्स के लिये टैण्डर आने के बाद भी कुछ फाइनल नही हो पाया है। हर विभाग में कोई भी रिक्त पद भरने के लिये मन्त्रीमण्डल की बैठक में प्रस्ताव लाये जाते हैं। जबकि यह एक सतत प्रक्रिया है जो स्वत: ही चलती रहनी चाहिये। इससे यह सामने आता है कि अधिकारी हर छोटे काम पर भी कबिनेट की मोहर लगवा रहे हैं जो एक तरह से सरकार पर विश्वास की कमी को दिखाता है। मुख्यमन्त्री ने अपने बजट भाषण में जिन नयी योजनाओं को शुरू करने की बात की थी उनमें से अभी अधिकांश की अधिसूचनाएं तक जारी नही हुई हैं। ऐसे में केन्द्र से जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्रदेश को मिलने का दावा किया गया था वह अब महज जुमला साबित होने वाला है। इसी तरह जिन नौ हजार करोड़ की योजनाओं के केन्द्र से मिलने का दावा मुख्यमन्त्री और जेपी नड्डा करते आये हैं उनकी व्यवहारिकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगने का खतरा मडराता नजर आ रहा है। क्योंकि यह सारी योजनाएं एडीवी से पोषित होनी है और पर्यटन के मामले में एडीवी ने जो नाराजगी जाहिर की है उसका असर इन योजनाओं पर पड़ने की पूरी संभावना है। भ्रष्टाचार के मामले में जो सरकार अपनी ही पार्टी के आरोप पत्र पर गंभीर न हो वह अन्य मामलों में क्या करेगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। इस वस्तुस्थिति में लोकसभा चुनावों में सफलता मिलना लगातार संदिग्ध होता जा रहा है और इस परिदृश्य में जयराम की चुनौतीयां बढ़ती जा रही है।

अत्यन्त सन्तोषजनक रहा है।

राज्यपाल ने किया पीड़ित मानवता की सेवा का आह्वान

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म और कार्य नहीं है और जो लोग पीड़ित मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, वे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं।

राज्यपाल हमीरपुर जिला के भोटा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य (एसएमएस)

सेवा कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर के एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन प्रयास सोसायटी की सहायता से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आरम्भ करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कार्यक्रम के उद्देश्य जिसके तहत जिले के लोगों को उनके घर–द्वार के निकट निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, को भी सराहा। उन्होंने कहा कि एसएमएस सेवा 40 अलग–अलग चिकित्सा प्रशिक्षणों के संचालन के लिए अति आधुनिक मोबाइल पैथोलॉजी प्रयोगशाला का उपयोग करती है और इसके माध्यम से लोगों को सभी प्राथमिक सेवाएं व दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस एसएमएस सेवा की अनेक अनूठी उपलब्धियां हैं और इसके लाभार्थियों में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं शामिल हैं।

उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर की प्रदेश में वहृद स्तर पर खेल गतिविधियां आरम्भ करने के प्रयासों की भी सराहना की तथा कहा कि इससे युवा अपना समय खेल गतिविधियों में लगाएं और नशे की आदत से दूर रह कर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश भ्रमण योजना भी अनुराग ठाकुर की एक अच्छी पहल है, इससे बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से जारी रहने चाहिए, क्योंकि इनका मानवता की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने अनुराग ठाकुर को इन प्रयासों के लिए बधाई दी तथा विश्वास जताया कि लोग इनसे लाभान्वित होंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एसएमएस सेवा एक मोबाइल मेडिकल इकाई शामिल है, जो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के दूरदराज गांव में अपनी सेवाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयन्ती 14 अप्रैल, 2018 को आरम्भ किया गया और कुछ ही माह के दौरान एसएमएस सेवा से 51 हजार से अधिक लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध हुई। उन्होंने कहा कि इस सुविधा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस नई सोच के तहत योजना को आरम्भ करने के लिए सांसद अनुराग ठाकुर को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने खेल महाकुंभ की भी पहल की है, जिसमें 25 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सांसद भारत दर्शन योजना भी आरम्भ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 250 बच्चे चयनित किए गए हैं।, जो देश भर के महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करेंगे ताकि वे ज्ञान व नई सोच के साथ आगे बढ़ सकें।

विधायक कमलेश कुमारी ने राज्यपाल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रयास सोसायटी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की प्रेरणा से आरम्भ की गई थी और वे इस सोसायटी की संस्थापक सदस्य हैं। उन्होंने सांसद अनुराग ठाकुर का जिले में आदर्श स्वास्थ्य सेवा आरम्भ करने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि एसएमएस सेवा निःस्वार्थ भाव से सभी के लिए उपलब्ध है।

प्राकृतिक खेती पर प्रदेश की प्रथम किसान परिचर्चा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कृषकों का आहवान किया कि वे प्राकृतिक खेती को समर्पण एवं ईमानदारी के साथ अपनाएं ताकि उत्पादन एवं भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े। आचार्य देवव्रत डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, सोलन में प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर आयोजित किसान परिचर्चा को संबोधित कर रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि अनुसंधानों ने यह सिद्ध किया है कि प्राकृतिक खेती भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है तथा मानव के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि वे प्राकृतिक कृषि के संबंध में स्वयं अनुभव करने के उपरांत ही किसानों को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे 25 वर्ष तक रसायनिक खाद युक्त कृषि एवं जैविक खेती करने के उपरांत प्राकृतिक खेती की ओर प्रवृत हुए तथा इसके परिणाम ने उन्हें किसानों को प्राकृतिक खेती की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक कृषि प्रकृति के मूल तत्वों मूलतः देसी गाय पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य तत्व भी प्रकृति से ही लिए गए हैं। देसी गाय के मात्र एक ग्राम गोबर में 300 करोड़ से अधिक लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। यह जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। देसी गाय के गोबर के उपयोग से प्राकृतिक रूप से केंचुओं की बढ़ोत्तरी होती है जो भूमि को दीर्घावधि के लिए कृषि योग्य बनाकर वर्षा जल संग्रहण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि खाद के लिए प्रयोग में लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के रसायन आरंभ में पैदावार बढ़ाते हैं किन्तु धीरे–धीरे भूमि को बंजर बना देते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे पदम श्री डॉ. सुभाष पालेकर द्वारा प्रचारित प्राकृतिक खेती की विधि अपनाएं। यह विधि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है तथा इसमें रसायनिक खाद की अपेक्षा जल भी काफी कम प्रयुक्त होता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कृषि के उत्पादों के विपणन के लिए भी योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे प्राकृतिक खेती के प्रचार–प्रसार के लिए समूह बनाकर कार्य करें।

राज्यपाल ने कहा कि रसायन खाद युक्त कृषि कैंसर जैसे भयावह रोग को बढ़ावा दे रही है। शोध के

अनुसार गत एक से डेढ़ वर्ष में कैंसर रोगियों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। प्राकृतिक कृषि के उत्पाद इस दिशा में भी मनुष्य एवं अन्य जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्रदेश सरकार देसी गाय की खरीद को बढ़ावा देने के लिए शीघ्र ही प्रावधान करने जा रही है। किसानों को देसी गाय क्रय करने के लिए 25 हजार रुपये का उपदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देसी गाय कृषि के साथ–साथ किसान की आय वृद्धि में भी सहायक बनेगी। देसी गाय के दूध की गुणवत्ता पूरे विश्व में सिद्ध हुई है।

डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एचसी शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए कहा कि प्राकृतिक खेती के संदर्भ में राज्य में यह प्रथम किसान परिचर्चा आरंभ की गई है। शीघ्र ही ऐसी परिचर्चाएं राज्यभर में आयोजित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 80 विकास खण्डों में से 79 विकास खण्डों में 2547 कृषक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने प्राकृतिक कृषि को पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। केन्द्र सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं में प्राकृतिक खेती के लिए धन भी उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है।

शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश्वर चंदेल ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

Himachal Pradesh
Public Work Department
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tender on the form NO 6 &8 are invited by the Executive Engineer Nalagarh Division HP PWD Nalagarh on behalf of the Governor Of Himachal Pradesh From the approved and eligible contractors enlisted in HP PWD, in the appropriate class for the work mentioned below in the presence of contractor or their authorized representative.

Time schedule of tender:-
(1)The last Date & time of receipt of Application for tender Form 23-01-2019 up to 11.00 AM.
(2) The last date of issue of tender form: 24-01-2019 up to 4.00 P.M
(4) The date of opening of tender: 24-01-2019 at 11.00 A.M

Earnest money in the shape of National Saving certificate/ Time Deposit accounts/ Saving accounts in any of the Post Office/ Bank in H.P duly pledged in favour of the Executive Engineer, HP PWD Nalagarh must be accompanied with the tender documents.

The conditional tender and the tender received without earnest money will be summarily rejected. The Executive Engineer reserves right to accept or reject any or all tenders ,the tenders shall be kept open for 120 days.

The contractor should be registered as dealer Under HP VAT/ sale Tax Act 1968 and also produce sale tax clearance certificate from the Excise and Taxation Department.

Sr. No.	Name of Work	Estimated Cost	E/Money	Time	Cost of form
1	Special repair of health sub center Building at vaid Ka Johar Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	197202	4000	One month	350
2	Special repair of health sub center Building at Patith Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	204644	4300	One month	350
3	Special repair of health sub center Building at Dang Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	112055	2700	One month	350
4	Special repair of health sub center Building at Reroo Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	105991	2100	One month	350
5	Special repair of health sub center Building at Bhangla Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	163682	3345	One month	350
6	Special repair of health sub center Building at Kumarhatti Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	352940	7500	One month	350
7	Special repair of health sub center Building at Manjholi Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	162733	3700	One month	350
8	Special repair of health sub center Building at Barrian Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	85166	2000	One month	350
9	Special repair of health sub center Building at Khera Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	137582	3600	One month	350
10	Special repair of health sub center building at Rampur Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	204644	4200	One month	350
11	Special repair of health sub center Building at Nahar Singh Tehsil Nalagarh Distt Solan (H.P)	160557	3200	One month	350
12	A/R & M/O Link road from Abharni to Souri K.M 0/0 to 2/250 (SH C/O retaining wall in K.m 1/900 to 1/915 under deposit	221214	4424	One month	350
13	A/R & M/O to police station Building at baddi (SH Repair to roof, Plaster and painting and other small repair work	363953	7280	One month	350
14	A/R & M/O to residential Building in Police Station Building at Baddi (SH repair to plaster and painting and other small repair work)	150065	3100	One month	350
15	A/R & M/O SP office at Baddi (SH P/L Bituminous concrete in open area of parking in Surrounding of SP office Baddi	160418	3210	One month	350

Following documents should accompany the application for tender:-
1. The tender forms will be issued to those contractors whose performance is not found satisfactory.
2. Earnest money should be accompanied with application without earnest mony will not be entertained.
3. The photo copy of G.S. T No /Vat/ EPF/Enlistment Number should be attached with application otherwise tender form will not be issued.
4. The contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand.

Adv. No.3872/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक– बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक–जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार–ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDERS

Sealed item/percentage rate tenders on form 6 & 8 for the following works are invited by the **Executive Engineer, Kumarsain Division, HP.PWD,** Kumarsain from the experienced contractors enlisted with HPPWD for B&R works so as to reach in this office on or before **23.01.2019 up to 3:00 AM** and will be opened on same day at **03:30 PM** in the presence of intending contractors or their authorized representatives who may wish to be present.
The application for issue of tender form shall be received on **22.01.2019 up to 4:00 P.M.** The tender form shall be issued against cash payment (non refundable) on **23.01.2019 up to 1:00 PM.** The earnest money must accompany with each application in the shape of Time deposit receipt/FDR and the deposit receipt of any post office or any recognized bank in HP duly pledged in the name of undersigned. The contractors who did not deposit the earnest money their tender shall summarily be rejected. The undersigned have the right to reject the tender without assigning any reason.

1. Name of Work:-C/O link road to village Challa to Shilla Ropa via Nizara Kantal & Phaladhar Km.0/000 to 5/120 (SH:- Formation Cutting 5/7 mtrs wide road in Km.2/290 to 2/570). Estimated Cost: Rs.4,79,693/- Earnest Money: Rs.9600/- Time: - Three Months.
2. Name of Work:- C/O link road to village Challa to Shilla Ropa via Nizara Kantal & Phaladhar Km.0/000 to 5/120 (SH:- Formation Cutting 5/7 mtrs wide road in Km.3/195 to 3/435). Estimated Cost: Rs.4,71,678/- Earnest Money: Rs.9500/- Time: - Three Months.
3. Name of Work:-Repair of Govt. Sr. Sec. School at Baragaon (SH:- P/L Cement Plaster, Red sand flooring, distempering & Kota Stone etc). Estimated Cost: Rs.4,81,506/- Earnest Money: Rs.9700/- Time: - Three Months.
4. Name of Work:-C/O Jamjhat to Dhalli road Km.0/000 to 0/600(SH:-C/O PCC R/Wall at Rd.0/495 to 0/510). Estimated Cost: Rs.2,99,301/- Earnest Money: Rs.6000/- Time: - Two Months.
5. Name of Work:-A/R & M/O on link road to village Aroth Km.0/000 to 2/800(SH:-C/O RCC Hume Pipe Culvert at Rd.1/045 along with wing walls). Estimated Cost: Rs.1,27,574/- Earnest Money: Rs.2600/- Time:- One Month.

Terms and conditions: -
1. The contractors shall produce their latest Registration/Renewal of their Registration/G.S.T Registration Number /PAN Number /E.P.F Registration Number along with their application.
2. The single/conditional tender will be rejected.
3. The offer shall remain valid up to 90 days

Adv. No.3882/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री का केन्द्र से 53 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली में केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक की और सैद्धांतिक रूप से राज्य के लिए स्वीकृत किए गए 53 राज्य मार्गो को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया, जिसके लिए

मंत्रालय को पहले ही एलाइनमेंटस (सरेखण) प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने सरकाघाट – घुमारवीं और रानीताल – कोटला राज्य राजमार्गो को नए राष्ट्रीय राजमार्गो के रूप में अधिसूचित करने के अतिरिक्त सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत शेष पांच राष्ट्रीय राजमार्गो को मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने ठियोग बाईपास के लिए अनुमानों को मंजूरी देने के अतिरिक्त विकास और समुचित रखरखाव के लिए ठियोग – हाटकोटी सड़क मार्ग को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने का आग्रह किया। उन्होंने एनएचआईआईपी चरण – 2 के तहत हमीरपुर – मंडी (एनएच – 70) और पांवटा साहिब – गुम्मा – फीड्ज पुल (एनएच – 72) को शामिल करने के लिए मंत्रालय की मंजूरी मांगी और कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्य की जीवन रेखाएं हैं और राज्य के भीतर कनेक्टिविटी का सबसे बेहतर साधन हैं। इसलिए इन परियोजनाओं पर तीव्र कारवाई बेहतर कनेक्टिविटी का मार्ग प्रशस्त करेंगी।

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को कालका – सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के फोरलेन कार्य की धीमी प्रगति के बारे में भी अवगत कराया जो राज्य की राजधानी में आने वाले पर्यटकों के लिए यातायात की भीड़ और असुविधा का कारण है। उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि मटौर – शिमला (एनएच – 88) और पठानकोट – मंडी (एनएच – 20) पर कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने नादौन – हमीरपुर और ब्रह्मपुखर शिमला (एनएच – 88), पठानकोट – मंडी (एनएच – 20) की स्थिति में सुधार के लिए अनुरोध किया क्योंकि इन सड़कों का कोई उचित रखरखाव नहीं हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि किरतपुर साहब – नेरचौक (एनएच – 21) पर काम रोक दिया गया है और कहा कि पिंजौर – बद्दी – नालागढ़ फोरलेन परियोजना के कार्य में देरी हो रही है। हालांकि, उन्होंने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करने का आग्रह किया क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र के लिए जीवन रेखा है, जो एक बड़ा फार्मा हब है और देश का 37 प्रतिशत दवा उत्पादन यहां हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग पर वाहनों की भारी आवाजाही है, इसलिए इस सड़क मार्ग पर तेज गति से निर्माण कार्य करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से राज्य सरकार द्वारा पहले से प्रस्तुत किए गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों के दृष्टिगत धनराशि प्रदान करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि पठानकोट – मंडी पर काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और इसके लिए 27 करोड़ रुपये पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को यह भी अवगत करवाया गया कि जल्द ही किरतपुर साहब – नेरचौक पर मुरम्मत का कार्य शुरू करने का प्रयास किया जाएगा और कहा कि सरकार द्वारा भेजी गई केंद्रीय सड़क निधि के तहत परियोजनाओं को जल्द ही मंजूरी दी जाएगी।

केंद्र से हिमाचल को एक और महिला भारतीय रिजर्व बटालियन की मांग

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की और उनसे राज्य में महिलाओं की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महिला सशक्तिकरण के लिए हिमाचल प्रदेश को एक और महिला भारतीय रिजर्व बटालियन (आईआरबी) स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर रही है। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें चौबीस घंटे गुडिया हेल्पलाइन और शक्ति बटन ऐप की शुरूआत तथा जिलों में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करना शामिल हैं।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि वर्तमान में राज्य में सात आईआरबी हैं, जिनमें से एक महिला बटालियन है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य के लिए एक और बटालियन को मंजूरी दी जाती है, तो यह राज्य द्वारा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सार्थक करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वर्णिम हिमाचल दृष्टिपत्र – 2017 को नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है और इसे पूरी तरह से लागू किया है। जय राम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री से पिछले साल मॉनसून के दौरान राज्य को हुए भारी नुकसान के लिए धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि अंतर – मंत्रालय की एक टीम ने नुकसान का आकलन करने के लिए राज्य का दौरा किया था। उन्होंने जल्द से जल्द धनराशि जारी करने का आग्रह किया।

केंद्रीय गृह मंत्री ने ध्यानपूर्वक उनकी मांगों को सुना और इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह और उपआवासीय आयुक्त विवेक महाजन भी इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ थे।

एसजेवीएन ने मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के 147 छात्रों को दी छात्रवृत्तियां

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकान्त तथा एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश के 147 छात्रों को मेधावी छात्रवृत्तियां प्रदान की। चयनित छात्रों को 24,000/- रुपए राशि के छात्रवृत्ति चैक प्रदान किए गए।

एसजेवीएन अपनी सीएसआर की पहल 'एसजेवीएन रजत जयंती मेधावी

छात्रवृत्ति योजना' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018 – 19 के लिए अपने प्रचालन वाले राज्यों से 12वीं कक्षा के 250 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर रहा है। शिमला में आयोजित एक समारोह में हिमाचल प्रदेश के 147 मेधावी छात्रों को एसजेवीएन फाऊंडेशन द्वारा छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। उपर्युक्त के अलावा अन्य राज्य जहां एसजेवीएन की परियोजनाएँ प्रगति के विभिन्न चरणों में है नामत: उत्तराखंड, बिहार तथा महाराष्ट्र में भी एसजेवीएन के संबंधित कार्यालय बाकी 103 छात्रवृत्तियां मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे।

एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, नन्द लाल शर्मा ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी से स्वागत किया और बताया कि सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से अमल में लाने के लिए एसजेवीएन फाऊंडेशन का गठन किया गया है। फाऊंडेशन द्वारा छात्रों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने और विभिन्न विधाओं में उच्च अध्ययन प्राप्त करने में उनकी मदद करने के उदेश्य से वर्ष 2012 में 'एसजेवीएन रजत जयंती मेधावी छात्रवृत्ति योजना' की शुरूआत की गई। 12वीं कक्षा के इन मेधावी छात्रों का चयन सीबीएसई, आईसीएसई तथा राज्य शिक्षा बोर्ड स्कूलों से किया जाता है। तदुपरांत इन चयनित छात्रों को अपना कोर्स पूरा करने तक प्रतिमाह रुपए 2000/- की छात्रवृत्ति दी जाती है। एसजेवीएन इस योजना के तहत 1387 मेधावी छात्रवृत्तियां प्रदान कर चुका है।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना का उदेश्य बीपीएल परिवारों के छात्रों तथा दिव्यांगों को उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना है जिसके लिए इन श्रेणियों के छात्रों के लिए क्रमश: 30% और 10% छात्रवृत्तियों के संवितरण का विशेष प्रावधान है।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति, सूर्यकान्त ने छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने एसजेवीएन प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि निगम के सीएसआर कार्यक्रमों के तहत शिक्षा के क्षेत्र में की गई यह पहल देश के मानव संसाधन को सशक्त मानव संसाधन में परिवर्तित करने में सहभागिता निभा रही है। एसजेवीएन द्वारा दी जा रही इन छात्रवृत्तियों के माध्यम से कई राज्यों के बच्चों को शिक्षा के बेहतरीन अवसर मिल रहे हैं जिससे वैश्विक शैक्षणिक मानचित्र में भारत अपना नाम रोशन करने में सफल रहेगा।

एसजेवीएन अपनी सीएसआर तथा सततशीलता संबंधी योजनाओं को एसजेवीएन फाऊंडेशन के माध्यम से क्रियान्वित करता है। फाऊंडेशन छह शीर्षों नामत: स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा तथा दक्षता विकास, अवसंरचना तथा सामुदायिक विकास, सततशील विकास, स्थानीय संस्कृति, विरासत तथा खेलों का संवर्धन और संरक्षण तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं विपदाओं के दौरान सहायता के तहत विभिन्न पहलें करता है।

छात्रवृत्ति वितरण समारोह में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल वीरेन्द्र सिंह सहित निदेशक (वित्त) ए. एस बिंद्रा, निदेशक (कार्मिक) गीता कपूर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, श्याम सिह नेगी भी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए कटिबद्ध: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए सरकार राज्य की निवेश क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए इस वर्ष जून माह के दौरान एक मैगा औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने भारतीय उद्योग परिसंघ के उपाध्यक्ष हरीश अग्रवाल के साथ एक परिचर्चा के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर मीट को सफल बनाने में भारतीय उद्योग परिसंघ की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हरीश अग्रवाल ने मैगा सम्मेलन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री को भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्य भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

पट्टा महलोग के जनमंच कार्यक्रम में आई 314 शिकायतें व मांगें

शिमला/शैल। कृषि, जनजातीय विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा की अध्यक्षता में सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पट्टा बारियां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पट्टा महलोग में आयोजित जनमंच में लगभग 3000 लोग उपस्थित रहे। जनमंच कार्यक्रम में कुल 314 शिकायतें एवं मांगें प्राप्त हुई। इनमें से 42 शिकायतें एवं मांगें पूर्व जनमंच अवधि में प्राप्ति हुई। 25 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा संभव बनाया गया। जनमंच में 25 जन्म प्रमाण पत्र, 84 हिमाचली प्रमाण पत्र तथा 20 आय प्रमाण पत्र बनाए गए। 89 व्यक्तियों को परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध करवाई गई। 4 हल्फनामें भी तैयार किए गए। 60 इन्तकाल किए गए। जनमंच में 112 व्यक्तियों का आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण किया गया।

जनमंच के अवसर पर आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नि:शुल्क शिविर में 325 रोगियों की स्वास्थ्य जांच की गई। 87 रोगियों के नेत्रों का परीक्षण किया गया। 63 रोगियों के विभिन्न परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित शिविर में 18 व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार अपंगता प्रमाण पत्र के लिए पंजीकृत किया गया। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के लिए 30 व्यक्तियों के कागजी कार्रवाई पूरी की गई। आयुर्वेद विभाग द्वारा आयोजित नि:शुल्क जांच शिविर में 267 रोगियों का स्वास्थ्य जांचा गया।

पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित नि:शुल्क जांच शिविर में 157 किसानों ने अपने पशुओं के परीक्षण के लिए पंजीकरण करवाया। विभाग द्वारा दूध के 25 नमूने एकत्र किए गए। मल के 29 नमूने एकत्र किए गए।

जो अग्नि हमें गर्मी देती है वह हमें नष्ट भी कर सकती है, लेकिन यह अग्नि का दोष नहीं है।।..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या राम मन्दिर पर 1992 दोहराया जायेगा

राम मन्दिर मुद्दे की सर्वोच्च न्यायालय ने दैनिक आधार पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का यह इन्कार उस समय आया है जब देश के कानून मन्त्री रविशंकर प्रसाद ने शीर्ष अदालत से इस मामले की सुनवाई फास्टट्रैक करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने टीवी साक्षात्कार में कहा है कि सरकार इस मामले में अदालत के फैसले का इन्तजार करेगी और इसमें अध्यादेश लाने का विकल्प नही चुनेगी। भाजपा/संघ के लिये राम मन्दिर निर्माण एक लम्बे अरसे से केन्द्रिय मुद्दा चला आ रहा है। दिसम्बर 1992 में इसी प्रकरण पर भाजपा की चार राज्यों की सरकारें राष्ट्रपति शासन की भेंट चढ़ गयी थी। 1992 के बाद केन्द्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनी है। दो बार स्व. वाजपेयी के नेतृत्व में गठबन्धन की सरकार बनी थी। लेकिन 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जो प्रचण्ड बहुमत मिला है ऐसा शायद दूसरी बार नही मिले। इस बार भाजपा किसी सहयोगी पर निर्भर नही है। 2014 में यह वायदा भी किया गया था कि राममन्दिर का निर्माण उसकी पहली प्राथमिकता होगी। बल्कि आजतक संघ/जनसंघ भाजपा के जो भी हिन्दुवादी मुद्दे रहे हैं उन्हे अमली जामा पहनाने का इस बार ऐसा अवसर मिला था जो निश्चित रूप से फिर नही मिलेगा। महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जा सकता था भले ही वह राज्य सभा में लटक जाता लेकिन इससे भाजपा की नीयत पर किसी को भी सन्देह करने का अवसर न मिलता उल्टे विरोधी जनता के सामने जबावदेही की भूमिका में आ जाते। लेकिन इस पूरे शासनकाल में मोदी सरकार ने एक भी दिन ऐसा कोई कदम नही उठाया। इससे संघ/भाजपा की नीयत पर जो सवाल/सन्देह उभरे हैं उनका वर्तमान में कोई जबाव नही है।

राम मन्दिर के मुद्दे पर संघ विश्व हिन्दु परिषद, साधु समाज और कई भाजपा/सांसदो/मन्त्रियों के जो ब्यान आये हैं और आ रहे हैं वह एकदम प्रधानमन्त्री के स्टैण्ड से अलग हैं। यह सभी लोग लोकसभा चुनाव से पहले मन्दिर के निर्माण की बातें कर रहे हैं। सरकार पर इस संद्धर्भ में कानून लाने की बात की जा रही है। इसके लिये केवल अध्यादेश लाने का ही विकल्प बचा है क्योंकि सामान्य विधेयक लाकर उसे कानून बनवा पाने की अब वक्त नही बचा है और सरकार अच्छी तरह जानती है। इस परिदृश्य में प्रधानमन्त्री का अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करना 1992 दोहराये जाने का स्पष्ट संकेत बन रहे हैं। ऐसे में यह सवाल और अहम हो जाता है कि क्या यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है यह सही में प्रधानमन्त्री और इन अन्यों के बीच गंभीर मतभेद चल रहे हैं क्योंकि अब तक जो कुछ सरकार बनने के बाद घटा है वह इसी ओर संकेत करता है कि यह सब कुछ रणनीतिक है। क्योंकि जब भी संघ/भाजपा और मोदी के कुछ मन्त्रीयों के विवादित के ब्यान आते थे तब प्रधानमन्त्री रस्मी नाराजगी और चुप रहने की नसीहत का ब्यान देते रहे जिसका व्यवहार में कोई अर्थ नही रहा। देश जानता है कि मण्डल के विरोध में उठा आरक्षण विरोधी आन्दोलन कितना उग्र हो गया था। उसमें आत्मदाह तक हुए। वी पी सिंह सरकार गिरने के साथ ही यह आन्दोलन बन्द तो हो गया लेकिन आरक्षण के खिलाफ भावना और धारणा बनी रही। अब जब मोदी सरकार आयी तब फिर कई राज्यों से आरक्षण को लेकर आवाजें उठी। मांग की गयी कि या तो हमें भी आरक्षण दो या सबका बन्द करो। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक जा पहुंचा और शीर्ष अदालत ने फैलसा दे दिया लेकिन मोदी सरकार ने संसद का सहारा लेकर यह फैसला बदल दिया। इससे भाजपा सरकार और संघ की नीयत और नीति पर सवाल उठे हैं यही आचरण धारा 370 को लेकर सामने आया हैं इस तरह ऐसे कई मुद्दे हैं जहां संघ/भाजपा की कथनी और करनी का फर्क खुलकर सामने आ गया है।

इस परिदृश्य में आज राम मन्दिर को लेकर यह सवाल उठता है कि सर्वोच्च न्यायालय से आज जो इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई करने की मांग की जा रही है क्या यह मांग और प्रयास 2014 में मोदी सरकार बनने के साथ ही नही हो जाना चाहिये था? लेकिन उस समय ऐसा नही किया गया क्योंकि उस समय कोई चुनाव नही होने जा रहे थे। आज चुनावों की पूर्व संध्या पर राम मन्दिर को लेकर जो वातावरण समाज में खड़ा किया जा रहा है उसके परिणाम क्या होंगे यह तो आने वाला समय ही बातायेगा। लेकिन जो कुछ भी घटता नज़र आ रहा है वह शायद देशहित में नही होगा। लगता है राम मन्दिर को लेकर 1992 को दोहराने की नीयत और नीति अपनाई जा रही है।

मनोहर लाल के लिए हरियाणा फतह इस बार आसान नहीं होगा

गौतम चौधरी

कायदे से हरियाणा विधानसभा का चुनाव तो लोकसभा चुनाव के बाद होना है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव भी लोकसभा के साथ ही करा लेना चाहती है। तर्क कई दिए जा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा या पुष्टि नहीं हो पायी है। इसलिए यह मान लेना कि हरियाणा का विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होगी इसकी संभावना फिलहाल कम ही दिख रही है। चुनाव जब भी हो लेकिन राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है।

सरसरी तौर पर देखें तो प्रदेश में तीन राजनीतिक शक्तियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी–कांग्रेस और तीसरी पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल। भारतीय जनता पार्टी, केन्द्र तथा राज्य में सत्तारूढ है। बीते विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने प्रदेश में दो तिहाई बहुमत से सत्ता हासिल की थी। प्रदेश की कुल 90 सीटों में से 47 विधानसभा सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया था। यह भाजपा के लिए अप्रत्याशित और चमत्कार से कम नहीं था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल–इनेलो, को 19 सीटें मिली और कांग्रेस, जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सत्तारूढ थी उसे मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा।

फिलहाल कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। हालांकि प्रदेश में अभी भी कांग्रेस और इनेलो की तुलना में भाजपा संगठित और व्यवस्थित है लेकिन केन्द्र सरकार की नीतियों और जाट–सैणी मतदाताओं की नाराजगी ने भाजपा को कमजोर किया है। यह भाजपा के लिए खतरनाक संकेत है। पिछले चुनाव में भाजपा को मुस्लिम मतदाताओं को छोड़, सभी जातियों का वोट मिला था और यही करण है कि भाजपा अपार बहुमत से सत्ता में आयी। इस बार प्रदेश की प्रभावशाली जातियां भाजपा से खफा दिख रही है। इसलिए आने वाले समय में भाजपा को कई मोर्चो पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

दूसरी ओर भाजपा विरोधी दलों की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मसलन भारी मारा–मारी है। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, इनेलो अपने परिवारिक कलह से परेशान है, तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अपने चार नेताओं की आपसी जंग में उलझी है। अभी हाल ही में इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने अपने सांसद पोते, दुष्यंत चौटाला को पार्टी से निकाल दिया। दुष्यंत चौटाला ने भी मोर्चा खोलते हुए अपनी नई पार्टी बना ली। इसलिए इनेलो से भाजपा को चुनौती मिलने की संभावना अब कम ही दिख रही है। खबर तो यह भी है कि दुष्यंत की नई पार्टी पर अभी से भाजपा डोरा डालने लगी है। दुष्यंत और भाजपा के बीच जो कुछ भी चल रहा है, वह स्पष्ट तो नहीं है लेकिन जानकारों का कहना है कि अभी हाल ही में संपन्न स्थानीय निकाय चुनाव में दुष्यंत के समर्थकों ने भाजपा का सहयोग किया। अगर इस खबर में सत्यता है तो फिर भाजपा को प्रदेश में एक नया साथ मिल जाएगा। इससे भाजपा को कितना लाभ मिलेगा यह कहना थोड़ा कठिन है लेकिन इस नए साथी के सहयोग से भाजपा जाट मतदाताओं में विभाजन तो करवा ही सकती है, जिसका सीधा लाभ भाजपा को होगा। हालांकि इनेलो ने मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया है। हरियाणा में दलित मतदाता, वोटिंग को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते रहे हैं लेकिन चौटाला परिवार की लड़ाई के कारण फिलहाल इनेलो भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, अपितु इस लड़ाई से भाजपा को फायदा ही होता दिख रहा है।

भाजपा को बड़ी चुनौती कांग्रेस से मिलने की संभावना है। वैसे फिलहाल प्रदेश कांग्रेस चार भागों में बंटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मजबूती से एक धरे का नेतृत्व कर रहे हैं और अपने सांसद बेटे चौधरी दीपेन्द्र सिंह हुड्डा को राजनीति में स्थापित करते जा रहे हैं। दूसरा धरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अशोक तवंर का है। तीसरा धरा केन्द्रीय प्रवक्ता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का है और चौथे धरे का नेतृत्व किरण चौधरी कर रही हैं। इन चारों नेताओं की आपसी लड़ाई जग–जाहिर है। इसके अलावा अंबाला की पूर्व सांसद, हरियाणा में कांग्रेस का दलित चेहरा शैलजा का भी अपना गुट है। ऐसे में कांग्रेस फिलहाल तो गुटबाजी के कारण कमजोर दिख रही है लेकिन प्रकृति के अनुकूल चुनाव तक कांग्रेस संगठित हो जाती है तो फिर भाजपा के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करेगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने समझौता करा दिया और देखते ही देखते कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की सत्ता भाजपा से छीन ली। ऐसी ही संभावना हरियाणा में भी दिख रही है। भाजपा का डर चारो नेताओं को है। खासकर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर भाजपा का बड़ा दबाव है। मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हुड्डा के प्रति ज्यादा आक्रामक है। ऐसी परिस्थिति में हुड्डा समझौता कर सकते हैं और जब हुड्डा समझौता करेंगे तो कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व का गतिरोध लगभग समाप्त हो जाएगा। ऐसे में कांग्रेस, सैणी, जाट, विष्णोई, दलित और ब्राहमण समीकरण को साध कर भाजपा को पटखनी देने में सक्षम हो कसती है।

कुल मिलाकर देखें तो हरियाणा का आसन्न विधानसभा चुनाव एक बार फिर से तीन राजनीतिक ताकतों के बीच लड़ी जाएगी। इसमें मुख्य लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी। वैसे इनेलो ने चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश तो की है लेकिन चौटाला परिवार के आपसी झगड़े ने फिलहाल उसे कमजोर कर दिया है। जो भी हो हरियाणा विधानसभा चुनाव पर केन्द्र की नीतियों का प्रभाव भी पड़ेगा, साथ ही अगर लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर भी प्रश्न खड़ा हो कसता है। तब प्रदेश में कांग्रेस मजबूत चुनौती के साथ उभरेगी। जो भी हो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए हरियाणा फतह इस बार आसान नहीं होगा।

बांग्लादेश चुनाव परिणाम भाजपा के लिए केस स्टडी हो सकते हैं

अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो 2019 भाजपा के लिए एक आसान लक्ष्य और विपक्ष के लिए एक असम्भव चुनौती के रूप में एकतरफा खेल दिखाई दे रहा था आज एक रोमांचक युद्ध बन गया? भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले तीन राज्य भाजपा के हाथों से फिसल गए। इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच केवल सत्ता का हस्तांतरण का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी हस्तांतरण हुआ।

'डॉ नीलम महेंद्र'

वैसे तो आने वाला हर साल अपने साथ उत्साह और उम्मीदों की नई किरणें ले कर आता है, लेकिन यह साल कुछ खास है। क्योंकि आमतौर पर देश की राजनीति में रूचि न रखने वाले लोग भी इस बार यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि 2019 में राजनीति का ऊँठ किस करवट बैठेगा। खास तौर पर इसलिए कि 2019 की शुरुआत दो ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाओं से हुई जिसने अवश्य ही हर एक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा। पहली घटना, साल के पहले दिन मीडिया को दिया प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार जिसमें वे स्वयं को एक ऐसे राजनेता के रूप में व्यक्त करते दिखाई दिए जो संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के साथ ही लोकतंत्र की रक्षा के लिए मजबूत विपक्ष के होने में यकीन करते दिखे। इस दौरान वे अपनी सरकार की नीतियों की मजबूत रक्षा और विपक्ष का राजनैतिक विरोध पूरी 'विनम्रता' के साथ करते दिखाई दिए। कहा जा सकता है कि वो अपनी आक्रामक शैली के विपरीत डिफेंसिव दिखाई दिए। और दूसरी घटना थी बांग्लादेश के चुनाव परिणाम। दरअसल अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के हाल के चुनाव नतीजों में शेख हसीना को लगातार तीसरी बार मिली जबरदस्त कामयाबी ने भारतवासियों की ना सिर्फ कुछ पुरानी यादों को ताजा कर दिया बल्कि शायद इस देश के आम आदमी से लेकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तक को भी काफी हद तक सोचने के लिए मजबूर किया होगा। क्योंकि लगातार 10 साल तक शासन करने के बाद, विपक्ष के तमाम आरोपों और उनकी कुछ हद तक अलोकतांत्रिक कार्यशैली (दबंग सत्तात्मक भी कहा जा सकता है) के बावजूद, इन चुनावों में बांग्लादेश की आवाम ने जिस प्रकार शेख हसीना पर अपना भरोसा जताया है और वहाँ विपक्ष का एक प्रकार से सफाया हो गया है, यह भाजपा और विशेष रूप से नरेंद्र मोदी के लिए एक केस स्टडी हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार वहाँ के लोगों को आज की स्थिति में शेख हसीना के अलावा अपने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कोई अन्य चेहरा दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, उसी प्रकार भारत में भी 2014 के चुनाव ही 'मोदीमय' नहीं थे बल्कि उन आम चुनावों के बाद अनेक राज्यों से आने वाले लगभग हर चुनाव परिणाम पूरे देश में मोदी लहर पर अपनी मुहर लगाते जा रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि मोदी के विजय रथ को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि नोटबन्दी और जीएसटी जैसे कठोर निर्णयों के बावजूद जिस प्रकार उत्तरप्रदेश और गुजरात में भाजपा का परचम खुलकर लहराया और अन्य राज्यों में सहयोगियों के साथ मिलकर, उसने जहाँ एक तरफ भाजपा के हौसले बुलंद किए वहीं कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को हैरानी और हताशा के उस मोड़ पर

ला कर खड़ा कर दिया जहाँ उन्हें यह एहसास होने लगा कि अपने अपने विरोधों को भुलाकर अपने विरोधियों के साथ मिलकर ही उनके लिए 'मोदी' नाम की सुनामी का सामना करने का एकमात्र विकल्प है।

लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो 2019 भाजपा के लिए एक आसान लक्ष्य और विपक्ष के लिए एक असम्भव चुनौती के रूप में एकतरफा खेल दिखाई दे रहा था आज एक रोमांचक युद्ध बन गया? भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले तीन राज्य भाजपा के हाथों से फिसल गए। इन राज्यों में भाजपा और कांग्रेस के बीच केवल सत्ता का हस्तांतरण का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी हस्तांतरण हुआ। 2014 के बाद पहली बार मोदी आक्रामक नहीं आत्मरक्षा की मुद्रा में और राहुल आत्मविश्वास से भरे एक नए अवतार में दिखाई दिए।

तो जनाब समझने वाली बात यह है कि कुछ भी 'अचानक' नहीं होता। ना 'मोदी लहर' अचानक बनी थी और ना ही राहुल का यह नया अवतार। भाजपा जिस मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता पर काबिज हुई थी, उस मोदी को पहले एक लहर और फिर सुनामी बनने में 14 साल लगे थे। जी हाँ, और उसकी नींव पड़ी थी 2001 में जब वे पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तब देश तो छोड़ो गुजरात में भी वो कोई बड़ा नाम नहीं थे। लेकिन ये उनकी कार्यशैली ही थी जिसने गुजरात के लोगों को लगातार उन्हें ही मुख्यमंत्री चुनने के लिए विवश कर दिया। और वो मोदी का गुजरात म डल था जिसने उनकी कीर्ति पूरे देश में फैलाई। इसी गुजरात म डल और मोदी की छवि को भाजपा ने उसे पूरे देश के सामने रखकर 2014 का दाँव खेला जो सफल भी रहा। भाजपा ही नहीं देश को उम्मीद ही नहीं विश्वास था कि गुजरात की तर्ज पर अब दिल्ली की कुर्सी भी 2025 तक बुक है। लेकिन आज वस्तुस्थिति यह है कि 2019 की राह भी कठिन लग रही है। आखिर क्यों? इसका विश्लेषण हर राजनैतिक पंडित अपने अपने तरीके से कर रहा है। कोई वोट बैंक के गणित को दोष दे रहा है तो कोई मोदी सरकार की नीतियों को। कोई विपक्षी एकता को दोष दे रहा है तो कोई भीतरघात को। कुल मिलाकर कारण बाहर ही ढूढे जा रहे हैं भीतर नहीं। जबकि अपनी हार को जीत में वो ही बदल सकता है जो कमियाँ खुद में ढूंढता है परिस्थितियों में नहीं। अब समय कम है लेकिन कुछ बातें जो भाजपा से ज्यादा मोदी जी को समझनी आवश्यक हैं,

1. यह बात सही है कि भाजपा से वोटर का मोहभंग हुआ है

2. चूंकि 2014 में लोगों ने मोदी को चुना था, भाजपा को नहीं इसलिए यह मोहभंग मोदी से है भाजपा से नहीं।

3. लेकिन इसका कारण राजनैतिक से अधिक मनोवैज्ञानिक है

4. क्योंकि जब किसी लहर के बहाव में बहकर लोग मतदान करते हैं तो वो भावना से प्रेरित होता है राजनीति से नहीं

5. ऐसे में अधिकांश वो दल एकतरफा जीत हासिल करता है जिसके पक्ष में लहर होती है जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा मिला था और उसने स्पष्ठ बहुमत प्राप्त किया था

6. 2014 में देश में मौजूद मोदी लहर की भावना से भाजपा सत्ता में आई

7. लोगों ने मोदी की आक्रामक एवं एक कट्टर हिंदूवादी कर्मठ प्रशासक छवि को वोट दिया था जो उन्होंने पहले 2001 में गुजरात को भयानक भूकंप से उपजी तबाही और फिर गुजरात को 2002 के दंगों के बाद उपजी अराजकता से उबार कर देश के मानचित्र पर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश बनाकर कमाई थी।

8. लेकिन केंद्र में आते ही मोदी ने पहली गलती अपनी छवि बदलने का प्रयास कर के की। पूरे देश के जनमानस में अपने लिए स्वीकार्यता बनाने के उद्देश्य से 'सबका साथ सबका विकास' के नारे से अपनी कट्टर हिंदूवादी की छवि से बाहर निकलने का प्रयास किया। इसके बजाए अगर वो अपनी 'उसी छवि के साथ' सबका विकास करते तो उन्हें कहीं बेहतर परिणाम मिलते।

9. देश ने जब मोदी को चुना था तो देश की उनसे बहुत अपेक्षाएँ थीं जिन्हें उन्होंने भी 'अच्छे दिन आने वाले हैं' के नारे से काफी बढ़ा दिया था।

10. लेकिन उन्होंने दूसरी गलती यह की, कि लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने के बजाए उनसे अपेक्षाएँ करने लगे (कि वे उनके कठोर निर्णयों में उनका साथ दें)।

11. लोगों ने भी विपक्ष की आशा के विपरीत नोटबन्दी और जीएसटी जैसे कठोर निर्णयों के बावजूद मोदी की झोली उत्तरप्रदेश हरियाणा और गुजरात में भर दी। देश मोदी की अपेक्षाओं पर खरा उतरता गया और मोदी मदमस्त होते गए। लेकिन यह भूल गए कि उन्हें भी देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है।

12. वो अपने पारंपरिक वोट बैंक को टेकेन फॉर ग्रांटेड लेते गए, यह उनकी तीसरी और सबसे बड़ी भूल थी।

13. जो भाजपा कहती थी कि मुस्लिम उसे कभी वोट नहीं देते और जिसके वोट के बिना वो सत्ता में आई वो उस वोट बैंक में सेंध डालने की नीतियाँ बनाने में इतनी मशगूल हो गई कि अपने चुनावी मेनिफेस्टो को ही भूल गयी। देश यूनिफॉर्म सिविल कोड, 35A ,370, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास जैसे फैसलों का इंतजार करता रहा और यह तीन तलाक की लड़ाई लड़ते रहे।

14. जिस मिडिल क्लास के दम पर भाजपा सत्ता में आई उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पहले ही बजट में उसके सपने यह कहकर तोड़ दिए कि मध्यम वर्ग को अपना ख्याल खुद ही रखना होगा

15 जो स्वर्ण समाज उसका कोर वोटबैंक था उसे एट्रोसिटी एक्ट का तोहफा दिया।

16. मोदी यह अच्छी तरह जानते हैं कि भारत का मध्यम वर्ग ही वो एकमात्र ऐसा वोटबैंक हैं जो नैतिक मूल्यों के साथ जीता है और बिकाऊ नहीं है (जबकि उच्च वर्ग की नैतिकता वहाँ होती है जहाँ उनके स्वार्थ की पूर्ति होती है)। शायद इसलिए उन्होंने इसका सबसे ज्यादा फायदा भी उठाया लेकिन अब नुकसान भी उठा रहे हैं।

17. और सबसे बढ़ी भूल, मोदी समझ नहीं पाए कि जिन 'दलितों शोषितों वंचितों' का जिक्र वो अपने हर भाषण में करते हैं और जिनके लिए वे उज्ज्वला, सौभाग्य, आयुष्मान, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण जैसी योजनाएं लेकर अपना वोटबैंक बनाने की सोच रहे हैं, वो पुरूष एक शराब की बोतल और महिलाएं चार साड़ी के नशे में वोट डालते हैं सरकारी योजनाएं देखकर नहीं। क्योंकि यह उनकी मजबूरी है क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं हैं वे अखबार नहीं पढते और ना ही उनके साक्षात्कार सुनते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मोदी भूल गए, कि यह वो देश है जहाँ चुनाव काम के दम पर नहीं वोटबैंक और जातीय गणित के आधार पर जीते जाते हैं, जहाँ वोट विकास के नाम पर नहीं आरक्षण या कर्ज माफी के नाम पर मिलते हैं।

लेकिन 2014 में देश में मोदी का कोई वोटबैंक नहीं था अगर था तो केवल गुजरात में था फिर भी मोदी को पूरे देश में वोट मिले। क्यों? क्या किसी जाति विशेष ने दिया था? नहीं, बल्कि लोगों ने जाती का भेद भूला के वोट दिया था। क्या मोदी ने आरक्षण या कर्जमाफी का लालच दिया था? नहीं, लोगों ने विकास के नाम पर वोट दिया था। कुल मिलाकर मोदी की छवि के आकर्षण के आगे सभी चुनावी समीकरण गलत सिद्ध हुए। लेकिन अफसोस मोदी ने सत्ता में आते ही स्वयं को उसी छवि से मुक्त करने के प्रयास शुरू कर दिए जो आत्मघाती सिद्ध हुआ। इसलिये मोदी को समझना चाहिए कि लोगों का आकर्षण 'मोदी' से अधिक उनकी दबंग हिंदूवादी छवि के प्रति था। उन्हें शेख हसीना से सीखना चाहिए कि सबको साथ लेकर चलने के लिए इच्छाशक्ति की जरूरत होती है छवि बदलने की नहीं।

दीवार पर लिखी साफ इबारत को पढ़ने में मोदी–शाह को हिचक क्यों?

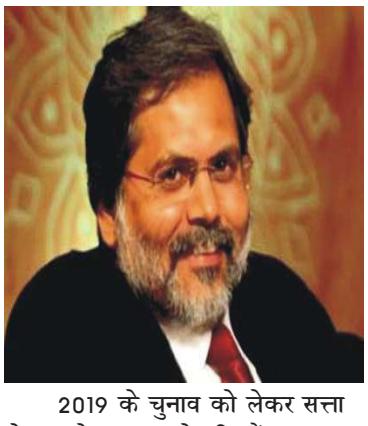

2019 के चुनाव को लेकर सत्ता के सामने सवाल दो ही हैं। पहला, ग्रामीण भारत की मुश्किलों को साधा कैसे जाये, दूसरा अयोध्या में राममंदिर पर निर्णय लिया क्या जाये। संयोग से जो रास्ता मोदी ने पकडा है वह उस वक्त भी साफ मैसेज दे नहीं रहा है जब आम चुनाव के नोटिफेकिशन में सौ दिन से भी कम का वक्त बचा है। ग्रामीण भारत को राहत देने के लिये तीन लाख करोड़ की व्यवस्था रिजर्व बैंक से की तो जा रही है लेकिन राहत पहुंचेगी कैसे। और राहत देने के जो माप–दंड मोदी सत्ता ने ही जमीन की माप से लेकर फसल तक को लेकर की है उसके डाटा तक सरकार के पास है नहीं तो तीन लाख करोड का वितरण होगा कैसे, कोई नहीं जानता। यानी अंतरिम बजट में अगर मोदी सत्ता एलान भी कर देती है कि खाते में रुपया पहुंच जायेगा तो भी सिस्टम इस बात की इजाजत नहीं देता कि वाकई एलान लागू हो जायेगा। यानी चाहे अनचाहे बजट में सुविधाओं की पोटली एक और जुमले में समा जायेगी। तो दूसरी तरफ राम मंदिर निर्माण पर जब मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही कोई निर्णय होगा तो उसके मर्म में दो ही संकेत दिखायी दिये। पहला, विहिप, बंजरंग दल या कट्टर हिन्दुवादी ताकतों को राज्य सत्ता की खुली छूट है लेकिन राम मंदिर निर्माण में कानून का राज चलेगा। दूसरा, भीडतंत्र या कट्टरता को राज्यसत्ता तभी तक सहुलियत देगी जब तक कानून का राज खत्म होने की बात खुले तौर पर उभरने ना लगे। यानी लकीर धुंधली है कि जो मोदी सत्ता को अपनी सत्ता मानकर कुछ भी करने पर आमादा है वह संभल जाये या फिर चुनाव तक संभल कर भीडतंत्र वाला रवैया अख्तियार करें। तो क्या अंधेरा इतना घना हो चला है कि मोदी अब इस पार या उस पार पर भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।

जाहिर है यहीं से मोदी सत्ता को लेकर बीजेपी के भीतर भी अब नये सवाल खड़े हो चले हैं जिसके संकेत नीतिन गडकरी दे रहे है। हालांकि गडकरी के पीछे सरसंघचालक मोहन भागवत की शह है इसे हर कोई नागपुर कनेक्शन से जोड़ कर समझ तो रहा है लेकिन गडकरी के पास भी जीत का कोई तुरुप का पत्ता है नहीं, सभी समझ इसे भी रहे है। इसलिये तत्काल में बीजेपी के भीतर से कोई बडा बवंडर उठेगा ऐसा भी नहीं है लेकिन चुनाव तक ये बंवडर उठेगा ही नहीं ऐसा भी नहीं है। और बीजेपी टूट की तरफ बढ़ जायेगी। संघ किसी बड़े बदलाव के लिये कदम उटायेगा। या मोदी –शाह की जोड़ी सिमट जायेगी। ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर बीजेपी संभाले अमित शाह और सरकार चलाते नरेन्द्र मोदी के उठाये कदमों से ही मिल सकता है। दोनों के ही कदम बीजेपी और संघ परिवार को बीते चार वर्ष से ये भरोसा जताकर उठाये जाते रहे कि उनके ना खत्म होने वाले अच्छे दिन अब आ गये। या अच्छे दिन तभी तक बरकरार रहेगें जब तक मोदी–शाह की जोड़ी काम कर रही है। ध्यान दें तो इस दौर में ना तो बीजेपी के भीतर से कभी कोई ऐसी पहल हुई जिसमें अमित शाह निशाने पर आ गये हों या मोदी के गवर्नेस को लेकर कोई सवाल संघ या सरकार के भीतर से उठा। यूपी चुनाव में जीत तक वाकई सबकुछ अच्छे दिन वाला ही रहा। यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम की लोकसभा सीट पर हुये उपचुनाव की हार के बाद कर्नाटक में हार और गुजरात में 99 सीटों की जीत ने कुछ सवाल जरुर उठा दिये लेकिन बीजेपी–संघ परिवार के भीतर अच्छे दिन है.... जो बरकरार रहेगें की गूंज बरकरार रही। लेकिन जिस तरह तीन राज्यो में हार को एंटी इनकंबेसी और तेलंगाना–मणीपुर को क्षेत्रिय दलों की जीत बताकर मोदी–शाह की जोड़ी ने आगे भी अच्छे दिनों के ख्वाब को संजोया या यह कहे कि बीजेपी–संघ परिवार को दिखाना चाहा उसमें पहली बार घबराहट, सरकार–पार्टी–संघ परिवार तीनों जगह दिखायी देने लगी। गडकरी ने अगर हार की जिम्मेदारी ना लेने के सवाल उठाये तो मोहन भागवत ने 2019 में प्रधानमंत्री कौन होगा पर ही सवालिया निशान लगा दिया। बीजेपी सांसदों के सुर अपने अपने क्षेत्रानुकुल हो गये। किसी को लगा राम मंदिर पर विधेयक लाना जरुरी है तो किसी को लगा दलित मुद्दे पर बहुत झुकना ठीक नहीं तो किसी ने माना गठबंधन के लिये सहयोगी दलों के सामने नतमस्तक होना ठीक नहीं। असर इसी का रहा कि एक तरफ अपनी कमजोरी छुपाने के लिये बीजेपी ने गठबंधन को महत्व देना शुरु कर दिया तो दूसरी तरफ मोदी सत्ता ने अतीत के हालातों को वर्तमान से जोड़ने की कोशिश की। मसलन बिहार में पासवान की पार्टी एक भी सीट जीत नहीं पायेगी पर छह सीटे पासवान को दे दी गई। जिससे मैसेज यही जाये कि साथी साथ नहीं छोड रहे है बल्कि ये सिर्फ सीटों के समझौते का संकट है। यानी बीजेपी के साथ सभी जुडे रहना चाहते हैं ये परसेप्शन बरकरार रखने की कोशिशें शुरु हो गई। लेकिन इसी के सामानांतर विपक्ष के महागठंबधन को जनता के खिलाफ बताकर खुद को जनता बताने की भी कोशिश मोदी–शाह ने शुरु की। लेकिन इस पहल से कहीं ज्यादा घातक अतीत के हालातों को नये हालातों पर हावी करने की सोच रही। जैसे तेजस्वी यादव के बाल्यकाल के वक्त हुये लालू के घोटालों में तेजस्वी यादव को ही आरोपी बनाया गया। इसी तरह राहुल गांधी भी बोफोर्स और इमरजेन्सी के कटघरे में खड़े किये गये। ध्यान दें तो जो छल गरीब किसान मजदूर का मुखौटा लगाकर कॉरपोरेट के हित साधने वाली नीतियों तले आम जनता से हुआ। कुछ इसी अंदाज में विपक्ष की सियासत को साधने के लिये अतीत के सवाल उठाये जा रहे हैं। यानी चाहे अनचाहे मोदी–शाह की थ्योरी तले एक थ्योरी जनता में भी बन रही है कि आज नहीं तो कल उनका नंबर आ जायेगा। जहां सत्ता उनसे छल करेगी। यानी खुद की कमजोरी छुपाने के लिये उठाये जाते कदम ही विपक्ष की कतार को कैसे बड़ा कर रहे हैं ये तीन राज्यों के जनादेश में झलका। यही हालात 2019 के जनादेश में छिपा हुआ है। क्योंकि पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ पर कार्यकर्ताओं की फौज को लगने की कमर्ठता वामपंथी रणनीति की तर्ज पर बीजेपी ने अपनाया। फिर 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बोजेपी से जुड़ने और तमाम तकनीकी जानकारी के साथ सत्ता भी हाथ में होने के बावजूद अगर बीजेपी तीन राज्यों में हार गई तो मतलब साफ है कि मोदी सत्ता ने समाज के किसी समुदाय को अपना नहीं बनाया। हर समुदाय को अच्छे दिन के सपने दिखाये गये, लेकिन हर किसी ने खुद को छला हुआ पाया। तो पार्टी चलाने का वृहत इन्फ्रास्ट्रक्चर हो या सत्ता के पास अकूत ताकत। जब जनता ही साथ जोडी नहीं गई तो फिर ये सब कैसे और कब तक टिकेगा। यानी सवाल ये नहीं है कि जातिय समीकरण में कौन किसके साथ साथ होगा, या राजनीतिक बिसात पर महागठबंधन की काट के लिये बीजेपी के पास सोशल इंजिनियरिंग का फार्मूला है। दरअसल साढ़े चार बरस में नीतियों के एलान तले अगर जनता का पेट खाली है, हथेली में रोजगार नहीं है तो फिर मुद्दा जातीय या धर्म या पार्टी के सांगठनिक स्ट्रक्चर को नहीं देखेगी। ये एहसास अब बीजेपी और संघ परिवार में भी हो चला है। आखरी सच यह भी है कि मोदी–शाह की जोड़ी सत्ता–पार्टी पर नकेल ढिला करेगी नहीं, और बाहर से उठी कोई भी आवाज बीजेपी की टूट की तरफ बढ़ेगी ही। और 2018 में चुनावी हार के बाद जो इबारत मोदी–शाह पढ नहीं पाये 2019 में तो दीवार पर किसी साफ इबारत की तरह वह लिखी दिखायी देनी लगी है। अब कोई ना पढ़े तो कोई क्या करे।

कंडा बंदी गृह में कविता पाठ,डीजीपी गोयल को आजीवन उपलब्धि सम्मान

शिमला/शैल। हिमालय साहित्य संस्कृति एवं पर्यावरण मंच की ओर से 30 दिसंबर को आदर्श केंद्रीय सुधार गृह कंडा में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें अन्य

कवियों के अलावा बंदी कैदियों ने भी कविता पाठ कर अपनी सृजना का परिचय दिया।

कवि गोष्ठी में बंदियों में से चेतन, ओम प्रकाश, किशोरी लाल, सुभाष और रमेश सहित पुलिस कर्मी उषा कुमारी ने भी कविताएं प्रस्तुत की। पुलिस कर्मी जितेंद्र ने राजस्थानी और पहाड़ी लोक गीत प्रस्तुत कर खूब वाहवाही बटोरी। हिमालय मंच ने बंदी कवियों को स्मृतिचिन्ह भी भेंट किये।

इस साहित्य समारोह में पुलिस महानिदेशक कारागार एवं सुधार सेवाएं सोमेश गोयल को हिमालय आजीवन उपलब्धि सम्मान–2018 से अलंकृत किया गया। यह सम्मान उन्हें मुख्य अतिथि व नागालैंड के पूर्व राज्यपाल अश्विनी कुमार द्वारा प्रदान किया गया।

मंच के अध्यक्ष एस आर हरनोट ने कहा कि सोमेश गोयल पुलिस प्रशासन के शीर्षस्थ पदों पर रहते हुए अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। विशेष तौर पर महा निदेशक जेल के पद पर रहते हुए जेल सुधारों एवं बंदियों को उनकी योग्यता अनुरूप हर हाथ को काम देकर उनके जीवन परिवर्तन के क्षेत्र में उनकी बडी भूमिका रही है। शिमला बुक कैफे के संचालन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है जिस वजह से कवि हर महीने कई लघु गोष्ठियां वहां कर पाते हैं। मंच की सदस्य एवं युवा लेखिका मोनिका छट्टू ने सोमेश गोयल का विस्तार से प्रशस्ति वाचन किया।

कार्यक्रम के आरम्भ में एस आर हरनोट ने कण्डा कारागार प्रशासन विशेषकर अधीक्षक सुशील ठाकुर और उप अधीक्षक जगजीत चौधरी समेत समस्त स्टाफ का इस आयोजन को कार्यरूप देने के लिए विशेष रूप से आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर लेखकों को सुधार गृह में चल रहे रोजगार मूलक उद्यमों और प्रदर्शनी का भ्रमण भी करवाया गया।

सम्मान समारोह के अवसर पर हिमालय मंच द्वारा कण्डा जेल के कैदियों के साथ शिमला और अन्य स्थानों से आये कवियों के साथ कविता पाठ का आयोजन किया गया।

इस आयोजन में मीनाक्षी पॉल विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रही। संगोष्ठी में शामिल अन्य कवियों में डॉ हेमराज कौशिक, डॉ विद्या निधि, आत्मा रंजन, रौशन जसवाल, गुप्तेश्वर नाथ उपाध्याय, कुलदीप गर्ग तरुण, नरेश देयोग, अनुराग विजयवर्गीय, कल्पना गांगटा, उमा ठाकुर, अंजलि दीवान, साधु शर्मा, अश्वनी कुमार, सुमन धनंजय, वंदना राणा, सुनील शर्मा, शांति स्वरूप शर्मा, जगदीश बाली और देशराज भी शामिल हुए।

मंच का सफल संचालन आत्मा रंजन द्वारा किया गया। उन्होंने वरिष्ठ लेखिका और समाजसेवी स्व.सरोज वशिष्ट के जेल में किये गए कार्यो को भी याद किया।

छोटे किसानो–बागवानों को सालों तक नही मिल पाता उपदान:विनोद

शिमला/शैल। पूर्व सरकार के कार्यकाल में वित्तीय नियमों को दरकिनार कर सरकारी योजनाओं में आबंटित करोड़ों के बजट की धनराशि को अनियमित तौर पर राज्य कोष से आहरण कर निजी/राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखे जाने का सरकार द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की इस कार्य के लिए सराहना करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं में आबंटित धनराशि जो प्रदेश के विकास कार्यो और लाभार्थी किसानों/बागवानों को राज्य कोष से आहरण करने के तुरन्त बाद वितरित की जानी अनिवार्य होती है, वह धनराशि पूर्व सरकार की गलत वित्तीय कुप्रबन्धन और अधिकारियों की अकुशलता के कारण बैंकों में पड़ी हुई है/थी, जिसका आंकड़ा पूरे प्रदेश में लगभग 1500 करोड़ रू. से ऊपर होने का अनुमान है । महासंघ तदर्थ कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि राज्य कोष से इस प्रकार के अनियमित करोड़ों की राशि के आहरण से योजनाओं में आबंटित बजट के खर्चे अप्रभावी हो जाते हैं, वहीं वित्तीय नियमों/कानून की उल्लंघना कर इसमें वित्तीय अनियमितितायें भी होती रही हैं। प्रदेश के मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और प्रदेश के वित्त सचिव द्वारा लिए गए इस पर कड़े संज्ञान से भविष्य में इस प्रथा को बन्द कर इसमें दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध वित्तीय नियमों की उल्लंघना में अनुशासनात्मक कारवाई प्रारम्भ करने का सरकार ने फैसला लिया है जो वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगायेगा और सरकारी योजनाओं का पैसा आवश्यकतानुसार तुरन्त विकास पर खर्च होने के साथ–साथ लाभार्थियों के खाते में सीधे जमा होगा।

विनोद कुमार ने कहा है कि आगामी बजट में सरकार से मांग है कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के छोटे किसानों बागवानों को मिलने वाले छोटे–छोटे उपदान राशियों का भुगतान एक तय समय सीमा के भीतर तुरन्त जारी करने की नीति का निर्धारण किया जाये, चूंकि अभी तक का यह अनुभव है कि विभाग के अधिकारी बड़े सरमायेदारों को करोड़ों के उपदान की राशियों को बिना कोई समय गवायें उन्हें उपलब्ध करवा देते हैं, जबकि छोटे किसान / बागवानों की छोटी–छोटी उपदान राशियां सालों तक उन्हें नहीं मिल पा रही हैं।

स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत से राज्य के 22 लाख लोग लाभन्वित होंगे सरकार का दावा

शिमला/शैल। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना 'आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो देशभर में 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई गई है, को हिमाचल प्रदेश में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया है। राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के सभी 4,83,643 पंजीकृत परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त योजना में सामाजिक– आर्थिक जाति जनगणना–2011 के आधार पर राज्य में चयनित 2,78,245 परिवारों को शामिल किया गया है। इस प्रकार यह योजना प्रदेश की लगभग एक–तिहाई आबादी यानि 22 लाख लोगों को लाभान्वित करेगी। यह दावा है राज्य सरकार का लेकिन इस दावे की संभावित सफलता पर उस समय प्रश्नचिन्ह लग जाता है जब जनमंच कार्यक्रम में अस्पतालों में डाक्टर उपलब्ध न होने की शिकायत आये और उस पर मंत्री को माफी मांगनी पड़े। यह स्थिति स्वयं मुख्यमन्त्री के अपने गृह जिले में घटी और इसके लिये मंत्री अनिल शर्मा को माफी मांगनी पड़ी।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये तक का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। लाभार्थी योजना का लाभ पूरे देश में किसी भी पंजीकृत अस्पताल में प्राप्त कर सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में डे–केयर सर्जरी सहित लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है। उपचार के लिए 183 अस्पतालों को पंजीकृत किया गया है जिसमें 153 अस्पताल सरकारी तथा 30 अस्पताल निजी क्षेत्र में हैं और आवश्यकतानुसार अन्य अस्पतालों को भी योजना में पंजीकृत किया जा रहा है।

योजना के तहत 52,207 लोगों को गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये कार्ड पंजीकृत अस्पतालों में जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोक मित्र केन्द्रों के माध्यम से भी गोल्डन कार्ड जारी करने का कार्य आरंभ किया गया है। लाभार्थी को अपना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर गोल्डन कार्ड बनावाने जाना होगा। लोक मित्र केन्द्र में 30 रुपए की राशि देकर यह कार्ड बनावाया जा सकता है। इस कार्य के निष्पादन के लिए प्रदेश में 3600 लोकमित्र सक्रिय हैं।

आयुष्मान भारत या अन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना में शामिल नहीं होने वाले परिवारों के लिए प्रदेश सरकार के अभिनव प्रयासों से दो योजनाओं मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना व हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक योजना को जोड़कर हिमकेयर योजना आरम्भ की है। योजना के अंतर्गत 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिकाएं, मिड–डे–मील कर्मी, अंशकालीक कर्मी, दिहाड़ीदार, अनुबंध कर्मचारी तथा आशा कार्यकताओं को शामिल किया गया है। अन्य परिवार 1000 रुपये देकर योजना में कार्ड बनवा सकते हैं।

योजना में एक परिवार के किसी भी सदस्य अथवा एक से अधिक सदस्यों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये के नि:शुल्क उपचार का प्रावधान है। पहली जनवरी, 2019 से ई–कार्ड जारी किए जा रहे हैं और यह कार्य 31 मार्च तक जारी रहेगा। योजना के तहत प्रदेश के लगभग 6.50 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष का गठन मुख्यमन्त्री के बजट भाषण 2018–19 के अनुरूप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद गरीब लोगों को सहायता प्रदान करना है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा।

कोष के अन्तर्गत गंभीर बीमारियों के ईलाज के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद गरीब लोगों को कोष के माध्यम से बहिरंग विभाग और अन्य विविध खर्चो की प्रतिपूर्ति करने का भी प्रावधान रखा गया है।

योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, पी.जी.आई. चण्डीगढ, सरकारी आयुर्विज्ञान अस्पताल सैक्टर–32, चण्डीगढ़, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, नई दिल्ली तथा प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत अस्पतालों में उपचार सहायता प्रदान की जाएगी।

कोष के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को मुख्यमंत्री के कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके लिए उपचार अनुमान प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अथवा बीपीएल कार्ड, प्रधानमन्त्री जन–आरोग्य योजना कार्ड/मुख्यमन्त्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना कार्ड/यूनिवर्सल हैल्थ प्रोटेक्शन कार्ड (यदि लाभार्थी इन योजनाओं मे पात्र है), पहचान पत्र, सत्यापित बिलों की प्रतियां (यदि लाभार्थी ने अपना ईलाज पहले करवा लिया है) जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। योजना के अन्तर्गत अभी तक 10 बच्चों को कॉक्लीयर इम्पलांट सर्जरी के लिए 55 लाख रुपए की राशि अनुमोदित की गई है।

वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में लोगों को जागरूक रहने का आग्रह

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी को जमा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है और यदि कोई कम्पनी जमा को स्वीकार करने का दावा करती है तो इस प्रकार का मामला संबंधित उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि उनके विरूद्ध कारवाई की जा सके।

उन्होंने कहा कि कुछ फर्जी कम्पनियां अथवा व्यक्ति सस्ते ऋण की पेशकश करती है, ऋण के बहाने प्रक्रिया फीस की मांग करती है, जमा करने पर उच्च दरों की पेशकश करती है अथवा फर्जी लॉटरी योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्तियों को प्रलोभन देती है। उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसी कम्पनियों के झांसे में नहीं आना चाहिए और अपने बैंक खाते का नम्बर अथवा विवरण व क्रेडिट/डेबिट कार्ड का पासवर्ड नहीं बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बैंक प्रबन्धक अथवा अधिकारी व कर्मचारी दूरभाष कालों के माध्यम से ऐसे मामलों में पूछताछ नहीं करता है।

प्रवक्ता ने आम जनमानस को इस प्रकार के भ्रामक संदेशों तथा फर्जी कालों के बारे में जागरूक रहने का आग्रह किया है, जो विभिन्न फर्जी योजनाओं का प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का फर्जी संदेश अथवा टेलिफोन कॉल प्राप्त करता है, उसे निगम विहार शिमला स्थित साईबर अपराध पुलिस स्टेशन को उनके दूरभाष नम्बर 0177–2620331 पर सम्पर्क करके अथवा cybercrcell &hp@nic-in पर मेल कर सूचित किया जा सकता है।

घूमल–अनुराग का शक्ति प्रदर्शन शुरू

अमित शाह की हमीरपुर पन्ना प्रमुख सम्मेलन में आने को हरी झंडी

शिमला/शैल। आगामी लोकसभा चुनावों से पहले 28 जनवरी को होने वाले हमीरपुर संसदीय हलके के पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में पार्टी के राष्टकृीय अधयक्ष अमित शाह की मौजूदगी का इंतजाम कर पूर्व मुख्यमंत्रे प्रेम कुमार धूमल व उनके पुत्र भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपना शद्रि प्रदर्शन करना शुरू कर दिया हैं।

लोकसभा के चार हलकों में से मंडी व सोलन में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन हो चुके हैं। भाजपा ने 23 दिसंबर को शिमला संसदीय हलके के सोलन में आयोजित हुए सम्मेलन में अमित शाह के आने का प्रचार जोरो पर किया था। लेकिन तीन राज्यों में भाजपा की सरकारें उखड़ जाने के बाद अमित शाह तो क्या केंद्र से कोई और बड़ा नेता भी इस कार्यक्रम में हाजिर नहीं हुआ। भाजपाइयों ने आखिर में नितिन गडकरी को मनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन वह विफल रहे। वहां भाजपा ने फिर केंद्रीय मंत्रे जगत प्रकाश नडडा को बुलाकर काम चलाया था।

पार्टी की ओर से मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि अमित शाह की ओर से 28 जनवरी को हमीरपुर संसदीय हलके के पन्ना प्रमुखें के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हरी झंडी मिल गई हैं।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 12 जनवरी को दिल्ली में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक के बाद हमीरपुर में यह सम्मेलन कहां करना हैं, इस बावत फैसला किया जाएगा। अभी स्थल का चयन नहीं किया गया हैं।

पूर्व मुख्यमंत्रे प्रेम कुमार धूमल के विधानसभा चुनावों में सुजानपुर से हार जाने के बाद यह पहला मौके है जब धूमल व अनुराग के अलावा उनके खेमे को अपनी ताकत का इजहार करने का मौका मिल रहा हैं। समझा जा रहा है कि इस सम्मेलन में जुटने वाली पन्ना प्रमुखों की भीड़ से तय हो जाएगा कि धूमल परिवार का हमीरपुर संसदीय हलके में अभी भी दबदबा कायम हैं या सुजानपुर विधानसभा हलके से धूमल केहार जाने के बाद उनकी सियासी जमीन खिसक गई हैं।

अब तक धूमल व उनके खेमे को जयराम ठाकुर सरकार के अलावा केंद्रीय मत्रे जगत प्रकाश नडडा , शांता कुमार ,आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अलग–थलग करने में पूरी ताकत लगाई हुई हैं। ऐसे में धूमल व अनुराग के लिए यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस सम्मेलन के लिए अमित शाह के आने की हरी झंडी मिलने पर धूमल व अनुराग ने पहला पड़ाव पूरा कर लिया हैं। अब से लेकर 28 जनवरी तक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए धूमल परिवार के अलावा बाकी धाड़े क्या करते हैं, इसका भी इल्म हो जाएगा।

इसके बाद शांता के गृह संसदीय हलके कांगड़ा में चौथा पन्ना प्रमुख सम्मेलन होना हैं।

राष्ट्रीय उच्च मार्गों के किनारे सुविधाएं विकसित करने के लिए 15 करोड़ स्वीकृत

शिमला/शैल। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय द्वारा प्रदेश के विभिन्न 52 राष्ट्रीय उच्च मार्गो के 52 चिन्हित स्थानों पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित करने की प्रदेश सरकार की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। केन्द्रीय मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण मनीषा नंदा ने बताया कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय उच्च मार्गो के किनारे यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्गो पर 52 स्थान पहले ही चिन्हित किए हैं। विकसित की जाने वाली सुविधाओं में महिलाओं तथा पुरूषों व विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए अलग से शौचालयों का निर्माण भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि परियोजना के अन्तर्गत व्यावसायिक स्थान, बैठने का स्थल, सहायक कक्ष, बेबी केयर कक्ष तथा प्राथमिक उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस परियोजना के तहत स्थल विकास, विद्युत स्थापन, सर्विस लेन का निर्माण तथा यात्रियों के लिए पार्किंग क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177–2805015, 94180–15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

क्या कांग्रेस की एकजुटता भाजपा के लिये चुनौती बन पायेगी

शिमला/शैल। क्या प्रदेश कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली शर्मनाक हार का बदला 2019 में ले पायेगी? उस समय केन्द्र और प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस की सरकारें थी और मण्डी से स्वयं वीरभद्र की पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह चुनाव मैदान में थी। लेकिन भाजपा उस समय चारों सीटें कांग्रेस से छीनने में सफल हो गयी थी। आज केन्द्र और राज्य में दोनों जगह भाजपा की सरकारें हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या वीरभद्र और कांग्रेस इस हार का बदला ले पायेंगे? यह सवाल तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वीरभद्र सिंह ने मण्डी से चुनाव लड़ने की हामी भर दी हो और इस हामी के बाद वह सुक्खु के साथ एक मंच पर भी आ गये हों। एक मंच पर आकर पहली बार यह देखने को मिला कि जब दोनों नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ एक शब्द नही बोला। वीरभद्र और सुक्खु के एक साथ आने से यह सन्देश तो चला ही गया है कि पार्टी नेतृत्व में अपने सारे मनभेद और मतभेद भुलाकर एकजुट खड़ा हो गया है। लेकिन क्या अकेले इस एक जुटता से ही 2014 के परिणामों को पलटने में सफल हो जायेंगे? यह सवाल भी इस

एकजुटता के साथ ही खड़ा हो गया है और यह सवाल इसलिये उठा है क्योंकि अभी जब सरकार अपना एक साल पूरा होने का जश्न मना रही थी उसी दिन कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ राज्यपाल को एक आरोपपत्र सौंपा।

यह आरोपपत्र आने के बाद कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठे हैं क्योंकि यह आरोप उसकी वरीयता के अनुरूप गंभीर नही थे। बल्कि जो आरोप ठाकुर राम लाल ने कुछ समय पूर्व बिलासपुर में एक पत्रकार वार्ता में लगाया था वह तक इस आरोप में दर्ज नही हो पाया। इस तरह के कई गंभीर मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन्हे यदि आरोपपत्र में शामिल किया जाता तो सरकार के लिये गंभीर परेशानी खड़ी हो सकती थी लेकिन ऐसा नही हो पाया है। इससे यही उभरता है कि या तो कांग्रेस आरोप पत्र बनाने में ही गंभीर नही और उसके लिये उसने ईमानदारी से कोई तैयारी ही नही की या फिर नीयत ही साफ नही थी। इस समय देश की राजनीति जिस मुहाने पर खड़ी है उससे यह आंशका बनती जा रही है कि आने वाले चुनावों में हिंसा तक हो सकती है। इस चुनाव में जो तथ्य पूर्ण आक्रामकता से जनता के सामने आयेगा उसी का पलडा भारी रहेगा।

इस परिप्रेक्ष में प्रदेश कांग्रेस ईकाई को प्रदेष्श सरकार के खिलाफ भी आक्रामक होना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय मुद्दों पर भी प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। लेकिन अभी तक इस तरह की तैयारी कांग्रेस की ओर से सामने नही आ पायी है। जबकि यह चुनाव पूरी तरह आक्रामक होने जा रहा है। इस समय कांग्रेस के खिलाफ सरकार के पास भाजपा के आरोप पत्र का एक बड़ा हथियार सुरक्षित पड़ा है। हालांकि सरकार इस पर अभी तक गंभीर नही है लेकिन यह गंभीरता कभी भी आ सकती है। फिर वीरभद्र सिंह और परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मनीलॉड्रिंग के मामले लबित चल रहे हैं। मनीलॉड्रिंग में ईडी वक्कामुल्ला चन्द्रशेखर की जमानत रद्द करवाने का प्रयास कर ही चुकी है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो पहले आक्रामकता अपना लेता है वह विरोधी पर भारी पड जाता है। ऐसे में यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस और सरकार में से कौन पहले आक्रामकता अपनाता हैं क्योंकि वीरभद्र और सुक्खु की एकजुटता से सियासी समीकरणों में जो बदलाव आया है उससे इस तरह की आक्रामकता की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं।

अन्ततः कालरा कॉम्लैक्स का कटा बिजली,पानी और लगा 50 हजार का जुर्माना

शिमला/शैल। शिमला के माल रोड पर बन रहे कालरा कम्पलैक्स का अन्ततः नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत ने बिजली पानी काटने के आदेश सुनाने के साथ ही इस पर पचास हजार का जुर्माना भी लगा दिया है। यही नही इसके निर्माण पर भी रोक लगा दी है और अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये यहां पर इसी व्यवसायी के खर्च पर निगम का कर्मचारी भी तैनात कर दिया है। अभी यह कम्पलैक्स काट दी है लेकिन बिजली काटने के बाद यहां पर जैनरेटर से काम चलाया जा रहा है लेकिन यहां पर एक रोचक सवाल यह खड़ा हो गया है कि बिजली काटने के आदेश कोई बिल की अदायगी न हो पाने के कारण नही हुए हैं बल्कि यह निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप न होने पर सज़ा के तौर पर हुए हैं। अब इस कॉम्प्लैक्स में जैनरेटर से बिजली दी जा रही है ऐसे में इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है कि इस पर क्या प्रावधान समाने आता है।

न्यायालय ने भी पिछले दिनों अवैध निर्माणों का कड़ा संज्ञान लेते हुए इनके बिजली, पानी काटने के आदेश किये हुए हैं और इन आदेशों की अनुपालना भी हुई है। इस तरह यह कालरा कॉम्पलैक्स हैरिटेज जोन में आता है और यहां पर केवल ओल्ड लाईनज़ पर ही निर्माण करने की अनुमति है। यहां पर भी गौरतलब है कि यहां के पुराने भवन में 1991 में आग लगी थी। उसके बाद जब यहां पर पुनः निर्माण की बात आयी थी तब यह मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक पहुंच गया था और अदालत ने नये निर्माण के लिये कुछ शर्ते लगा दी थी। तब इन शर्तो पर अमल न हो पाने के कारण यहां कोई निर्माण नही हो पाया था।

उसके बाद यह कॉम्पलैक्स कालरा के पास आ गया और 25.5. 2008 को इसके निर्माण का नक्शा पास करवाया गया। अब जब सरकार ने वर्ष 2000 में ही हैरिटेज जोन में नये निर्माणों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया था तब स्वभाविक है कि इसका नक्शा भी ओल्ड लाईनज पर ही स्वीकृति हुआ होगा। लेकिन अब जब यह निर्माण सामने आया तब इस पर स्वीकृत नक्शें से हटकर निर्माण करने के आरोप लगने शुरू हो गये। इन आरोपों का संज्ञान लेते हुए निगम ने कालरा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तुरन्त प्रभाव से काम बन्द करने के आदेश दिये। लेकिन इन आदेशों पर कोई अमल नही हुआ। निगम ने पहला नोटिस 11-7-2018 और अन्तिम नोटिस 2-11-18 को दिया तथा इस तरह चार नोटिस दिये। इस निर्माण में स्वीकृत नक्शे से हटकर कितना निर्माण हुआ है इस पर संबंधित जेई से लेकर निगम के वास्तुकार तक से रिपोर्ट ली गयी। जब लगातार नोटिस दिये जाने के बाद भी काम बन्द नही किया गया तब यह मामला आयुक्त की कोर्ट में आया और अन्ततः यह फैसला सुनाया गया। इस फैसले की अपील की जा रही है। अब सबकी नज़रें इस अपील पर आने वाले फैसले पर लगी हैं।

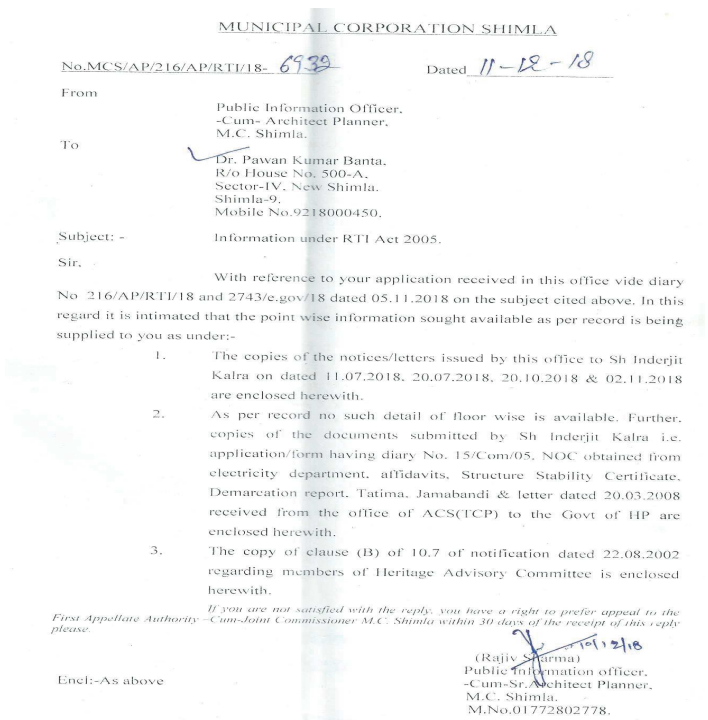

स्मरणीय है कि इस समय नगर निगम के पास इस तरह के निर्माणों के 960 मामले लंबित हैं इनमें कई मामले तो ऐसे भी है जहां पर रिटैन्शन पॉलिसी आने के बाद निर्माण बढ़ाये गये हैं लेकिन संयोगवश ऐसे निर्माणों की कम्पलीशन रिपोर्ट न तो गिनम में दायर हो पायी और न ही स्वीकृत हो पाये। अब एनजीटी का

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

No.MCS/AP/216/AP/RTI/18- 6932 Dated 11-12-18

From
Public Information Officer,
-Cum- Architect Planner,
M.C. Shimla.

To
Dr. Pawan Kumar Banta,
R/o House No. 500-A,
Sector-IV, New Shimla,
Shimla-9.
Mobile No.9218000450.

Subject: - Information under RTI Act 2005.

Sir,

With reference to your application received in this office vide diary No 216/AP/RTI/18 and 2743/e.gov/18 dated 05.11.2018 on the subject cited above. In this regard it is intimated that the point wise information sought available as per record is being supplied to you as under:-

1. The copies of the notices/letters issued by this office to Sh Inderjit Kalra on dated 11.07.2018, 20.07.2018, 20.10.2018 & 02.11.2018 are enclosed herewith.
2. As per record no such detail of floor wise is available. Further, copies of the documents submitted by Sh Inderjit Kalra i.e. application/form having diary No. 15/Com/05, NOC obtained from electricity department, affidavits, Structure Stability Certificate, Demarcation report, Tatima, Jamabandi & letter dated 20.03.2008 received from the office of ACS(TCP) to the Govt of HP are enclosed herewith.
3. The copy of clause (B) of 10.7 of notification dated 22.08.2002 regarding members of Heritage Advisory Committee is enclosed herewith.

If you are not satisfied with the reply, you have a right to prefer appeal to the First Appellate Authority -Cum-Joint Commissioner M.C. Shimla within 30 days of the receipt of this reply please.

Encl:-As above

10/12/18
(Rajiv Sharma)
Public Information officer,
-Cum-Sr.Architect Planner,
M.C. Shimla.
M.No.01772802778.

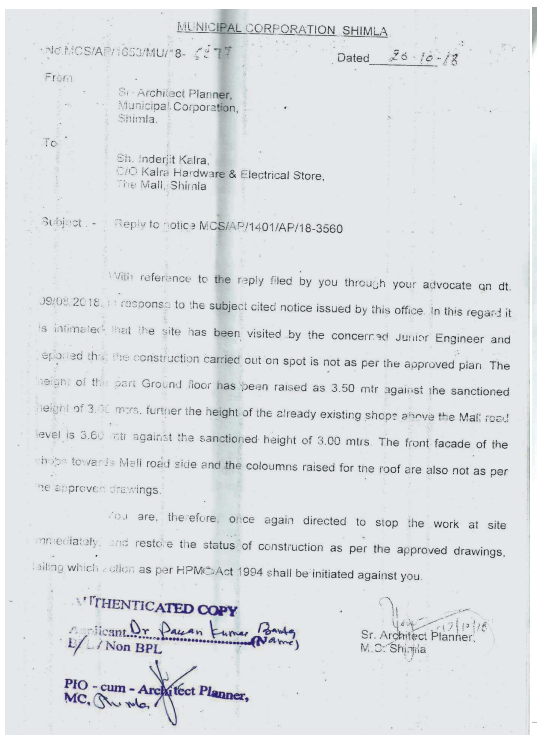

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA

No.MCS/AP/1653/MU/18- [illegible] Dated 26-10-18

From
Sr. Architect Planner,
Municipal Corporation,
Shimla.

To
Sh. Inderjit Kalra,
C/O Kalra Hardware & Electrical Store,
The Mall, Shimla

Subject : - Reply to notice MCS/AP/1401/AP/18-3560

With reference to the reply filed by you through your advocate on dt. 09/08/2018 in response to the subject cited notice issued by this office. In this regard it is intimated that the site has been visited by the concerned Junior Engineer and reported that the construction carried out on spot is not as per the approved plan. The height of the part Ground floor has been raised as 3.50 mtr against the sanctioned height of 3.00 mtrs, further the height of the already existing shops above the Mall road level is 3.60 mtr against the sanctioned height of 3.00 mtrs. The front facade of the shops towards Mall road side and the coloumns raised for the roof are also not as per the approved drawings.

You are, therefore, once again directed to stop the work at site immediately, and restore the status of construction as per the approved drawings, failing which action as per HPMC Act 1994 shall be initiated against you.

AUTHENTICATED COPY
Applicant Dr Pawan Kumar Banta (Name)
BPL / Non BPL
PIO - cum - Architect Planner,
MC, Shimla

Sr. Architect Planner,
M.C. Shimla

नगर निगम शिमला

[illegible] दिनांक [illegible]

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

Sh. Inderjit Kalra
c/o Exchange building
The Mall Road, Shimla

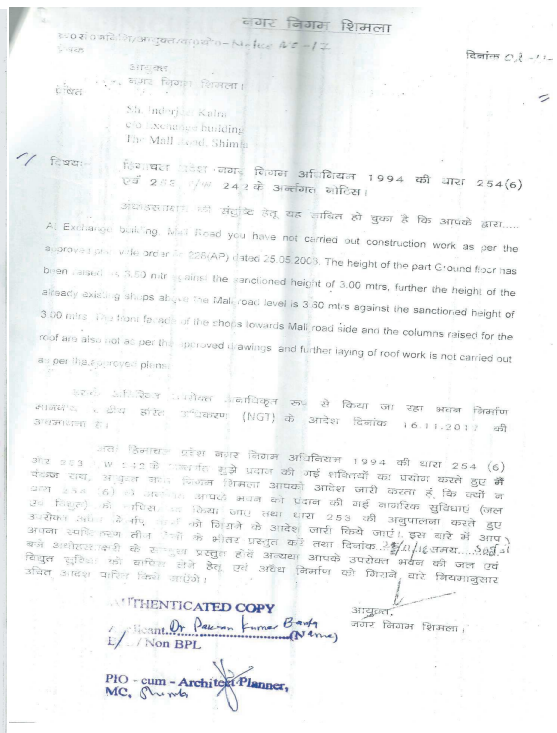

विषय:- हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 254(6) एवं 253 r/w 242 के अर्न्तगत नोटिस।

[illegible] की संतुष्टि हेतु यह साबित हो चुका है कि आपके द्वारा..... At Exchange building, Mall Road you have not carried out construction work as per the approved plan vide order no 228(AP) dated 25.05.2008. The height of the part Ground floor has been raised as 3.50 mtr against the sanctioned height of 3.00 mtrs, further the height of the already existing shops above the Mall road level is 3.60 mtrs against the sanctioned height of 3.00 mtrs. The front facade of the shops towards Mall road side and the columns raised for the roof are also not as per the approved drawings and further laying of roof work is not carried out as per the approved plans.

इसके अतिरिक्त उपरोक्त अनाधिकृत रूप से किया जा रहा भवन निर्माण माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश दिनांक 16.11.2017 की अवमानना है।

अतः हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 254 (6) और 253 r/w 242 के अर्न्तगत मुझे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पंकज राय, आयुक्त नगर निगम शिमला आपको आदेश जारी करता हूं कि क्यों न धारा 254 (6) के अर्न्तगत आपके भवन को प्रदान की गई नागरिक सुविधाएं (जल एवं विद्युत) को वापिस न किया जाए तथा धारा 253 की अनुपालना करते हुए उपरोक्त अवैध निर्माण को गिराने के आदेश जारी किये जाएं। इस बारे में आप अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के भीतर प्रस्तुत करें तथा दिनांक [illegible] समय [illegible] बजे अधोहस्ताक्षरी के सम्मुख प्रस्तुत होवें अन्यथा आपके उपरोक्त भवन की जल एवं विद्युत सुविधा को वापिस लेने हेतु एवं अवैध निर्माण को गिराने बारे नियमानुसार उचित आदेश पारित किये जाएंगे।

AUTHENTICATED COPY
Applicant Dr Pawan Kumar Banta (Name)
BPL / Non BPL
PIO - cum - Architect Planner,
MC, Shimla

आयुक्त,
नगर निगम शिमला।

निर्माणाधीन स्टेज के दायरे में आता है और निगम के नियमों के मुताबिक ऐसे निर्माण में कोई व्यवसायी गतिविधियां शुरू नही की जा सकती हैं। लेकिन निगम के नियमों को नजरअन्दाज करते हुए यहां पर सरेआम व्यवसायी गतिविधियां भी चल रही हैं। निगम कोर्ट के फैसेले पर अमल करते हुए बिजली बोर्ड ने यहां की बिजली जो

कालरा कॉम्पलैक्स माल रोड़ पर स्थित है और यह हैरिटेज जोन में आता है। इस क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 से ही नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। सरकार के इसी प्रतिबन्ध पर एनजीटी ने दिसम्बर 2017 में दिये फैसले में मोहर लगा दी है। एनजीटी के फैसले का अनुमोदन सर्वोच्च न्यायालय भी कर चुका है। प्रदेश उच्च

फैसला उन्ही निर्माणों पर लागू नही होगा। जिनकी कम्लीशन फैसला आने तक स्वीकार हो चुकी है अन्य पर नही। ऐसे में कालरा कम्पलैक्स के मामले में सबकी निगाहें इस पर लगी है कि निर्माणों में अवैधतता को रोकने के लिये अदालत, प्रशासन और सरकार क्या रूख अपनाते हैं क्योंकि कालरा को सरकार का नजदीकी माना जाता है।